Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVI, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम

विनोद कुमार विश्नोई *

*** एम.ए. नेट (राजनीति विज्ञान) ग्राम - समेलिया, पोस्ट घोड़ास, तह. मांडल, जिला भीलवाड़ा (राज.) भारत**

प्रस्तावना – राजस्थान, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हालांकि, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की साक्षरता दर अत्यंत निम्न थी, जो सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधक थी। 1947 में भारत की साक्षरता दर लगभग 18% थी, जबकि राजस्थान में यह और भी कम, लगभग 8-10% थी (Jagran Josh, 2024)। आजादी के बाद, भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए, जिनके परिणामस्वरूप 2022 तक राजस्थान की साक्षरता दर 69.7% तक पहुँच गई (News24, 2022)। यह रिसर्च पेपर राजस्थान में साक्षरता दर के विकास का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से आजादी के बाद से लागू किए गए प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के संदर्भ में। इसके अतिरिक्त, यह पेपर साक्षरता दर में सुधार की चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वतंत्रता से पहले, राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से रियासतों द्वारा संचालित थी।

रियासतों में शिक्षा का स्तर सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर था और यह अधिकांशत: उच्च वर्गों तक सीमित थी। महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के लिए शिक्षा तक पहुँच लगभग नगण्य थी। 1947 में स्वतंत्रता के समय, राजस्थान की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से भी कम थी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति और भी खराब थी।1951 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान की साक्षरता दर मात्र 8.02% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 12.9% और महिला साक्षरता केवल 2.9% थी (Wikipedia, 2007)। इस निम्न साक्षरता दर का कारण था शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी, सामाजिक असमानताएँ और आर्थिक पिछड़ापन। इसके बावजूद, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया और राजस्थान सरकार ने भी स्थानीय स्तर पर कई पहल शुरू कीं।

साक्षरता दर का विकास: आँकड़े और रुझानराजस्थान में साक्षरता दर में पिछले सात दशकों में वृद्धि हुई है। राजस्थान ने साक्षरता दर में निरंतर सुधार किया है, विशेष रूप से महिला साक्षरता में। हालांकि, 2011 की जनगणना के अनुसार, राजस्थान की महिला साक्षरता दर (52.7%) देश में सबसे कम थी, जो सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दर्शाता है (Jagran Josh, 2023)

भारत सरकार के साक्षरता कार्यक्रम आजादी के बाद, भारत सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम शुरू किए, जिनका प्रभाव राजस्थान में भी देखा गया।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988)राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (National Literacy Mission, NLM) की शुरुआत 1988 में हुई, जिसका उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाना था। इस मिशन के तहत राजस्थान में संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया। 1991 तक, राजस्थान के कई जिलों में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से अजमेर और उदयपुर जैसे क्षेत्रों में। NLM ने सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, जिससे साक्षरता दर 38.81% तक सर्व शिक्षा अभियान (2001)सर्व शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan, SSA) का शुभारंभ 2001 में हुआ, जिसका लक्ष्य 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था।

राजस्थान में SSA के तहत स्कूलों की संख्या में वृद्धि, मिड-डे मील योजना, और शिक्षकों की भर्ती जैसे कदम उठाए गए। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम किया और विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। 2011 तक, राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर 95% से अधिक हो गई (Know India, n.d.)।साक्षर भारत मिशन (2009)साक्षर भारत मिशन (Saakshar Bharat Mission) का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और वंचित समुदायों, को साक्षर बनाना था। राजस्थान में इस मिशन ने 404 जिलों में काम किया, जहाँ महिला साक्षरता दर 50% से कम थी (Adda247, 2023)। 2020 तक, इस मिशन ने राजस्थान में 3 लाख से अधिक महिलाओं को साक्षर बनाया (Bhaskar, 2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 20202020 में शुरू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने साक्षरता और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया। छम्द ने प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग, डिजिटल शिक्षा, और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। राजस्थान में छम्द के तहत डिजिटल कक्षाओं और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई, जिसने 2022 तक साक्षरता दर को 69.7% तक बढ़ाने में मदद की (News24, 2022)।

राजस्थान सरकार के साक्षरता कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई स्थानीय स्तर के कार्यक्रम शुरू किए, जो साक्षरता दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे। स्कूल चलो अभियान1999 में शुरू किया गया स्कूल चलो अभियान राजस्थान में बच्चों को स्कूल तक लाने का

एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इस अभियान ने विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया। 2001–2011 के बीच, इस अभियान ने स्कूल नामांकन में 30% की वृद्धि की और ड्रॉपआउट दर को 15% तक कम किया (Rajasthan Gyan n.d.)।बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2015)बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने राजस्थान में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। इस योजना के तहत, जालौर और सिरोही जैसे कम साक्षरता वाले जिलों में बालिकाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, साइकिल वितरण, और छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 2022 तक, राजस्थान में बालिका साक्षरता दर 56.5% तक पहुँच गई, जो 2011 के 52.7% से सुधार दर्शाता है (News24, 2022)।3. पढ़ना–लिखना अभियान (2020)2020 में शुरू किए गए पढ़ना–लिखना अभियान ने 15 वर्ष से अधिक आयु के 4.2 लाख निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा, जिनमें 3.15 लाख महिलाएँ थीं (Bhaskar, 2020)। इस अभियान ने सिरोही, बाड़मेर, और जालौर जैसे जिलों में विशेष ध्यान दिया, जहाँ साक्षरता दर सबसे कम थी। 2022 तक, इस अभियान ने 2 लाख से अधिक लोगों को साक्षर बनाया (Bhaskar, 2020)। डिजिटल शिक्षा पहलराजस्थान सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कक्षाएँ शुरू कीं। स्मार्ट विलेज और डिजिटल पंचायत पहल ने ग्रामीण समुदायों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया। 2025 तक, राजस्थान की 1000 से अधिक पंचायतें डिजिटल रूप से सशक्त हो चुकी हैं ।

राजस्थान में साक्षरता की क्षेत्रीय विविधता राजस्थान के विभिन्न जिलों में साक्षरता दर में काफी अंतर है। 2011 की जनगणना के अनुसाररूसबसे अधिक साक्षर जिला: कोटा (76.6%) – यह जिला कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध है (Jagran Josh, 2024)।सबसे कम साक्षर जिलारू जालौर (54.9%) – यह ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है (Jagran Josh, 2024)।महिला साक्षरता में अग्रणी: झुंझुनू (86.9% पुरुष साक्षरता के साथ)।आदिवासी क्षेत्र: उदयपुर और बांसवाड़ा में साक्षरता दर 60% से कम है, जो सामाजिक और भौगोलिक बाधाओं को दर्शाता है।

साक्षरता दर बढ़ाने में चुनौतियाँ सामाजिक असमानताएँ: राजस्थान में जाति, लिंग, और आर्थिक असमानताएँ साक्षरता को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव के कारण बालिका शिक्षा बाधित होती है।

वित्तीय कमी: स्कूलों में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की कमी, और शिक्षण सामग्री की अपर्याप्तता एक बड़ी समस्या है।

डिजिटल विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की कमी डिजिटल शिक्षा को सीमित करती है।आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच: बाड़मेर, सिरोही जैसे क्षेत्रों में भौगोलिक बाधाएँ शिक्षा की पहुँच को कम करती हैं।

महिला निरक्षरता: 2020 में, राजस्थान में 3.15 लाख महिलाएँ निरक्षर थीं, जो कुल निरक्षरों का 75% थीं (Bhaskar, 2020)।

शिक्षा की गुणवत्ता: साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कमी एक चुनौती है।

उपलब्धियाँ महिला साक्षरता में सुधार: 1951 में 2.9% से 2022 में 56.5% तक महिला साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

स्कूल नामांकन:SSA और स्कूल चलो अभियान ने प्राथमिक शिक्षा में 95% से अधिक नामांकन सुनिश्चित किया।

डिजिटल साक्षरता: स्मार्ट विलेज और डिजिटल पंचायत पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया।

सामुदायिक भागीदारी: कुदुम्बश्री मॉडल (केरल से प्रेरित) और स्थानीय NGOs ने साक्षरता अभियानों में सहयोग किया।

भविष्य के लिए सुझाव महिला साक्षरता पर ध्यान: विशेष रूप से जालौर, सिरोही, और बाड़मेर जैसे जिलों में बालिका शिक्षा और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

डिजिटल बुनियादी ढांचा: ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाना।

शिक्षा की गुणवत्ता: शिक्षक प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम सुधार पर जोर देना।

आदिवासी क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम: उदयपुर और बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में मोबाइल स्कूल और स्थानीय भाषा में शिक्षा।

वित्तीय निवेश: शिक्षा पर बजट आवंटन को बढ़ाकर स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना।

सामाजिक जागरूकता: बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाना।

निष्कर्ष:राजस्थान में साक्षरता दर में आजादी के बाद से उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो भारत और राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयासों का परिणाम है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षर भारत और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों ने साक्षरता को बढ़ावा दिया। हालांकि, सामाजिक असमानताएँ, वित्तीय कमी, और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं। भविष्य में, डिजिटल शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देकर राजस्थान की साक्षरता दर को और ऊँचा किया जा सकता है। यह न केवल सामाजिक–आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि राजस्थान को एक सशक्त और शिक्षित राज्य के रूप में स्थापित करेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. (2023). भारत में साक्षरता दर: बिहार में सबसे कम 61.8% और केरल में सबसे अधिक 94%. Retrieved from hindi current affairs
2. adda247.comBhaskar. (2020). 4.20 lakh illiterates in 33 districts of the state. Retrieved from
3. www.bhaskar.comJagran Josh. (2023). -भारत के 10 सबसे साक्षर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश. त्मजतपमअमक तिवउ
4. www.jagranjosh.com Jagran Josh. (2024). भारत के तीन सबसे कम साक्षर राज्य कौन–से हैं
5. www.jagranjosh.com know India. संक्षिप्त विवरण – साक्षरता.
6. knowindia.india.gov.inNews24. (2022). जानें किस राज्य की साक्षरता दर कितनी है.Retrieved from hindi.news 24online.comRajasthan Gyan. (n.d.).
7. राजस्थान जनगणना व साक्षरता – 2011. Retrieved from www.rajasthangyan.comState Election Commission, Rajasthan. (2025). Local Election Report 2025. Retrieved from sec.rajasthan.gov.inTestbook. (2023). राजस्थान की जनसंख्या और साक्षरता.
8. Testbook.com Wikipedia. (2007). List of Indian states and union territories by literacy rate. Retrieved from en.wikipedia.org